दिल्ली में पेय जल की समस्याएं

2874. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मे पेय जल की समस्या बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस मामले की जांच करने के लिए दो वर्ष पूर्व एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि समिति ने इस सम्बन्ध में सरकार को अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) समिति की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि 472 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन की मूल्यांकित मांग की तुलना में 409 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन सप्लाई किया जा रहा है । वर्तमान कमी 63 मिलियन गैलन प्रतिदिन है ।

(ख) से (ङ) दिल्ली को पेयजल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विकसित दीर्घावधि आयोजना प्रारम्भ करने के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति 10 दिसम्बर 1985 को गठित की गई थी । इसकी अब तक 5 बैठकें हुई हैं ।

Growing of recommended varieties of rapeseed and mustard

2975. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research has advised farmers to grow recommended varieties of rapeseed and mustard in the different parts of the country;

(b) if so, what are these varieties, and

(c) what is the total quantity of recommended varieties supplied to the farmers of different States so far and the acreage of land covered?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND CO-OPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) Yes, Sir. A list of recommended varieties if given in the enclosed Statement. (*See* below)

(c) During 1986-87, more than 44.800 quintals of certified/ quality seed of different rapeseed-mustard varieties were planned for distribution to the farmers of different States so as to cover an estimated area of about 9 lakh hectares in the country

.... **Statement** ..

List of rapeseed-mustard varieties recommended for cultivation in different parts of the country

MUSTARD. Seeta, Bhagirathi, Sarama, Varuna, Shekhar, Krishna, Kranti, Vaibhav, Vardan, Rohini, Patam mustard-67 Durgamani, Pusa Bold, Prakash, RH-30, RLM-198, RLM-514 RLM-619.

TORIA: M-27, TA—29, Agrani (B-54), BR-23, T-9, T-36, Bhawani, PT-30, PT-303, Sangam, TL-15 and DK-1.

BROWN SARSON: BS-2, BS-70, Pusa Kalyani, BSH-1, KOS-1:

YELLOW SARSON: Bonoy (B-9), 66-197-3, T-151, K-88. PS-66 and YSBH-24.

GOBHI SARSON: CLS1.

बड़े शहरों को प्रदूषित जल की पूर्ति

2876. **श्री शरद यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1987 के "नवभारत टाइम्स", दिल्ली संस्करण में "80 प्रतिशत आबादी को प्रदूषित पानी" शीर्षक के अन्तर्गत

प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जो जीवाणु या रसायनों से दूषित पानी की समस्या का सामना कर रहे महानगरों और बड़े शहरों के नाम क्या हैं और इस समस्या के दीर्घ-कालिक और अल्प-कालिक हल के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सामान्यत: महानगर तथा बड़े शहरों में पेयजल पूर्ण शोधन के पश्चात उपलब्ध कराया जाता है । प्रदूषण के किसी विशेष मामले में जल की कोटि सुनिश्चित करने के लिये उपचारी कदम उठाये जाते हैं । तथापि, यह समाचार चार राज्यों के चार जिलों में ग्रामों से लिये गये नमूनों के जल कोटि विश्लेषणों से सम्बन्धित है । ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय ने विश्लेषणों की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेजी हैं ।

Production of Vanaspati

2877. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the names of vanaspati manufactures in the country (State-wise) and quota prescribed for production during the last three years;

(b) State-wise names of manufacturers of vanaspati, who have produced vanaspati more than their prescribed quota (alongwith the difference of quantity in quota prescribed and actual production);

(c) whether this kind of excess production is permissible under the Essential Commodities Act; if so, the details thereof;

(d) if not, the action taken by Government against each of the manufacturer for violation of provisions of the said Act;

(e) whether this type of restriction, if any, on excess production, in the said Act creates scarcity of vanaspati in the country; and

(f) if so, the reasons for not removing such restrictions?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) A statement in this regard is enclosed. [*See* Appendix CXLIV, Annexure No 129].

Units can produce vanaspati upto 125 per cent of the licensed capacity.

(c) and (d) Under Essential Commodities Act, 1955, no action has been taken for excess production of vanaspati. However, administrative action has been taken against usage of imported oils in excess of the prescribed limit in the production of vanaspati.

(e) and (f) The vanaspati capacity already licensed is by and large adequate to meet the requirement of vanaspati.

Ownership rights to allottees of Nehru Nagar slum colony

2878. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2933 given in the Rajya Sabha on the 20th March, 1987 and state by when the allottees/ occupants of residential slum flats of Nehru Nagar would be provided the ownership rights?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): Ownership rights can be granted to